

महिला सशक्तिकरण एक सफल प्रयास—भारत सरकार के दृष्टिकोण से

डॉ० मो० इमरान आलम

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपनी परम्परागत दबू प्रकृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। इससे इस वर्ष विशेष में देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को नई गति प्रदान करने का प्रयास किया गया। उनके प्रति बढ़ रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं में कमी लाने, अधिकारों और नारी शक्ति के संबंध में उनके जागरूकता और चेतना विकसित करने हेतु सार्थक प्रयास किए जाने की घोषणाएँ की गईं। "महिला सशक्तिकरण वर्ष" में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार एक "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति" बनाई गई ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान समुचित विकास और समानता के लिए आधारभूत व्यवस्थाएँ निर्धारित किया जाना संभव हो सके।